प्रशासन के आदेश नहीं मान रही बैंक

नकारात्मक भूमिका से किसान मुसीबत में, मान्यवरों की प्रतिक्रिया

अमरावती,प्रतिनिधि, 18 जून - राज्य सरकार के कड़े निर्देश से प्रशासन पहली बार गंभीर नजर आ रहा है. किसानों को कर्ज वितरण के मामले में प्रशासन व बैंक आमने-सामने आ गए हैं. जिलाधीश अभिजीत बांगर के निर्देश पर परतवाड़ा के पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर पर अपराध दर्ज किया गया. इतना ही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सरकारी खाते बंद किए गए. इसके बावजूद सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अब तक मात्र 2 से 8 प्रतिशत ही फसल कर्ज वितरित किया है. प्रशासन के आदेशों को बैंक ठेंगा दिखा रही है. इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रस्तुत है मान्यवरों की प्रतिक्रिया.

मुझे जरा भी खबर नहीं

जिलाधीश की शिकायत पर किसी बैंक के मैनेजर पर कोई मामला दर्ज हुआ है, इसकी मुझे जरा भी खबर नहीं है. मगर बैंक किसानों को कर्ज दे रही है. किसान जिस बैंक में जा रहे हैं, वहां उन्हें कर्ज मिल रहा है. चारों ओर सरकारी यंत्रणा सक्रिय है. धीरे-धीरे कर्ज वितरण में बढ़ोतरी होगी. बैंकों के साथ हमारी चर्चा-मीटिंग हो रही है. हम बैंकों को महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे रहे हैं. किसानों को समय पर कर्ज उपलब्ध हो ऐसा नियोजन करने की दिशा में कार्य शुरु है.

जितेंद्रकुमार झा, लीड बैंक के मैनेजर

सरकार को कर रहे बदनाम

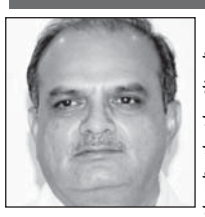

हम किसानों की संतान हैं. फिर भी बैंक किसानों को कर्ज नहीं देती, यह दुर्भाग्यजनक है. बैंक वाले भी किसानों की संतान हैं, मगर उन्हें किसानों के दर्द का एहसास नहीं. इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया था कि बैंकों की सुविधाएं आमजनता तक पहुंचें. बैंक को ऐसा लगता है कि किसान को अगर कर्ज दिया तो वह डुबा देंगे. बैंकों को सिर्फ व्यापारियों का फिक्स डिपॉजिट चाहिए. मगर हम जिन किसानों के भरोसे जिंदा हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है. बैंकिंग क्षेत्र मोदी व फड़णवीस सरकार को बदनाम कर रहा है.

दिनेश सूर्यवंशी, भाजपा जिलाध्यक्ष

सरकार का नहीं ध्यान

सरकार किसानों के हित में नहीं है. किसानों को मदद करने की उनकी कोई मंशा नहीं. जिले की अधिकांश बैंक किसानों को कर्ज नहीं दे रही हैं. इसकी कई शिकायतें जिलाधीश को सौंपी गयी हैं, मगर उसका कोई फर्क बैंकों पर नहीं हुआ है. सरकार केवल घोषणा कर रही है. घोषणा प्रत्यक्ष रूप में साकार नहीं की जा रही. किसानों की ओर सरकार का कतई ध्यान नहीं. सरकारी की नितियों के कारण किसान व सामान्य वर्ग परेशान है. यह सरकार उद्योगपतियों के हित का जतन कर रही है.

विधायक यशोमती ठाकुर, तिवसा

जिलाधीश की भूमिका सराहनीय

परतवाड़ा की पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर पर जिलाधीश की पहल से मामला दर्ज हुआ. मैं रक्तदान कर जिलाधीश का सत्कार करूंगा. जिले में पहली बार किसी बैंक पर अपराध दर्ज हुआ है. किसानों के हित में जिलाधीश की भूमिका सराहनीय है. इस कार्रवाई से अन्य बैंकों को सबक मिला है. धीरे-धीरे सुधार आएगा. बैंक केवल नीरव मोदी व विजय माल्या को पैसे देती थी. गरीब किसानों को पैसे नहीं देती. 23 जून को जनता दरबार लगा रहा हूं, उसमें बैंकों से संबंधित सभी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा.

विधायक बच्चू कडू, अचलपुर

4,397 संदिग्ध मरीजों के रक्त नमूनों की जांच

मलेरिया रोकथाम के लिए जनजागृति अभियान 30 तक

प्रतिनिधि, 18 जून

अमरावती- बारिश के दिनों में मलेरिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, जिसके चलते जिला मलेरिया विभाग ने इस वर्ष 1 से 30 जून तक जनजागृति अभियान शुरू किया. अभियान अंतर्गत 1 से 7 जून तक 4,397 संदिग्ध मरीजों की रक्त के नमूनों की जांच की गई है. हालांकि एक भी मलेरिया का मरीज विभाग को नहीं मिला.

बारिश में खुलेगी पोल

बारिश के दिनों में संसर्गजन्य बीमारियों का फैलाव अधिक होता है. जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हाथीरोग, प्लेप्टापायरेसीस आदि मरीजों में बढ़ोतरी होती है, इसलिए इस वर्ष इन बीमारियों पर प्रतिबंध व नियंत्रण पाने के लिए विभाग ने पहले ही संशयित मरीजों के नमूनों की जांच कराई. इतना ही नहीं तो इस अभियान अंतर्गत मलेरिया विभाग के वैज्ञानिक अधिकारी, स्वास्थ्य सेवक, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका द्वारा भी जनजागृति करने का दावा किया है. अब सवाल यह है कि विभाग द्वारा जनजागृति करने का दावा किया जा रहा है, किंतु बारिश में विभाग द्वारा की गई जनजागृति की पोल खुल जाती है. इन दिनों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि इर्विन में एक बेड पर 2-3 मरीजों पर इलाज कराने अस्पताल प्रशासन भी मजबूर होता है. ऍनाफिलीस मच्छरों की पैदावार गंदे पानी की बजाए स्वच्छ पानी में होता है, इसलिए विभाग द्वारा बारिश का पानी किसी भी फेंकी गई वस्तुओं में जमा नहीं होने पर जनजागृति की गई. बावजूद इसके नागरिकों द्वारा बारिश के दिनों भी स्वच्छ पानी भरकर रखा जाता है. कूलर का पानी भी खाली करने में आनाकानी की जाती है, इसलिए मच्छरों की पैदावार बढ़ती है, जबकि प्रशासन द्वारा गंदी नालियों को ही स्वच्छ करने जोर दिया जाता है.

10वीं पास छात्रों को तत्काल दें टीसी

अमरावती - 2017-18 से मनपा क्षेत्र में 11वीं के प्रवेश ऑनलाइन केंद्रीय पद्धति से किये जा रहे हैं. इसके लिए खासकर बायफोकल पाठ्यक्रम के लिए 10वीं पास विद्यार्थियों को तुरंत टीसी दी जाए, ऐसे आदेश सहायक शिक्षा उपसंचालक काले ने अमरावती संभाग के सभी शिक्षाधिकारियों को दिये हैं. उपरोक्त ऑनलाइन प्रवेश के बारे में मार्गदर्शन के लिए संबंधित संभागीय शिक्षा उपसंचालक कार्यालय में ऑफिस समय के दौरान सुबह 10 से 5 तक संपर्क केंद्र शुरु किये गये हैं. 11वीं में प्रवेश लेने इच्छुक सभी विद्यार्थियों ने ऑनलाइन प्रवेश अर्ज भरना अनिवार्य है. लेकिन राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विद्यार्थियों को मार्कलिस्ट नहीं दी गई है. इसलिए शाला द्वारा टीसी भी नहीं दी जा रही. ऐसे में बायफोकल पाठ्यक्रम का पहला राउंड मार्कलिस्ट वितरित होने के पूर्व ही होने वाला है. जिसकी वजह से टीसी नहीं रहने के कारण विद्यार्थी प्रवेश लेने से विमुख रह सकते हैं. फलस्वरूप, ऑनलाइन मार्कलिस्ट देखकर प्रधानाध्यापकों ने उनके स्तरपर 21 जून के पूर्व ही संबंधित विद्यार्थियों को टीसी प्रदान करना अपेक्षित है. ताकि 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया में कोई रोड़ा न बने. इसके बारे में शिक्षाधिकारियों ने निर्देश दें, ऐसे आदेश शिक्षा उपसंचालक विभाग के सहायक संचालक तेजराव काले ने अमरावती संभाग के सभी शिक्षाधिकारियों को दिये हैं.

सैकड़ों नर्सों ने किया योग प्राणायाम

सीएस डॉ. श्यामसुंदर निकम का सहयोग,डॉ. रोमा बजाज प्रशिक्षक

प्रतिनिधि, 18 जून

अमरावती- अंतर्राष्ट्रीय नैचरोपैथी संस्था की जिला समन्वयक डॉ. रोमा बजाज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग का प्रचार-प्रसार करने के साथ योग प्रशिक्षण लिया जा रहा है. आयएनओ व सूर्या फाऊंडेशन (आयुष मंत्रालय का सहयोग) द्वारा यह उपक्रम लिया जा रहा है. डॉ. रोमा बजाज द्वारा 10 योग शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के बाद शहर व जिले में अलग-अलग योग क्लासेस ली जा रही हैं. सोमवार को सीएस डॉ. श्यामसुंदर निकम के सहयोग से इर्विन व डफरीन अस्पताल की सैकड़ो नर्सों को योग व प्राणायाम सिखाया. उनका योग प्रशिक्षण का सिलसिला बदस्तूर जारी है. इस अवसर पर शिवानी नाईक, अंजलि लांजेवार, पुष्पा कवानी, प्रतीक्षा कोकणे, रोहिनी भगत, सोनाली विधाते, पूजा हानकर, स्नेहा माहोरे, रुचिता वानखड़े, सुरभि सोनकुसरे, हिनु तामगाडगे, दीपाली भाकरे, काजल आखरे, तृष्णा शेंडे, संगीता बारब्दे, नरेंद्र बडोले, प्रणल हाडवे, राहुल कारंजेकर, ऋषिकेश वाघ, रुचिता शेरकी, खुशाली उमाठे, कोमल यावले, अमिता भालवीर, प्रतीक्षा मदनकर, स्मिता वानखड़े, मृणाल वंजारे, शिल्पा चव्हाण, पूनम सुरकर, नेहा पजारे, वैशाली वाजगे, पूजा धुर्वे, कोमल शिंदे, मोर्या वनकर, वैष्णवी इंदाने, रोशनी हजारे, पल्लवी दुर्गे, किरण श्रावणकर, प्रियंका बोड़खे, कल्याणी चोरवणकर सहित सैकड़ों नर्स व प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे.

अमरावती : योग प्राणायाम के दौरान उपस्थित डॉ. रोमा बजाज व अन्य.

बडनेरा में महाराणा प्रतापसिंह जयंती की रैली निकली

स्थानीय वीर राणा मंडल का आयोजन, हिंदू एकता का विशाल दर्शन

प्रतिनिधि, 18 जून

बडनेरा - हिंदू सूर्य वीर शिरोमणि महाराणा प्रतापसिंह की जयंती निमित्त ऐतिहासिक रैली स्थानीय वीर राणा मंडल द्वारा बडनेरा में निकाली गई. इस रैली में लोगों ने हिंदू एकता के विशाल दर्शन किया. इस रैली के बंदोबस्त में करीब 1 हजार से ज्यादा पुलिस कर्मी, कमांडो, स्पेशलफोर्स तैनात थे. बडनेरा के इतिहास में यह पहली बार हुआ. मानो पूरा बडनेरा पुलिसमय बन चुका था.

यहां के लोगों ने रैली में सहभागी होकर हिंदू एकता का सराहनीय दर्शन करवाया. जिसके लिए शिवराय कुलकर्णी, सांसद आंनदराव अड़सूल, सुनील खराटे, चंदू पाटिल, बजरंगदल के बाबू गहरवाल, निरंजन दुबे, बडनेरा के सभी नेताओं का रैली आयोजन समिति ने आभार माना. अमरावती महानगर व बडनेरा प्रखंड के सभी बजरंगियों ने रैली में सहयोग किया व रैली की शुरुआत से लेकर समापन तक रैली के साथ रहकर शोभा बढ़ाई. पूरी रैली हिंदुत्ववादी बन गई. उसके प्रति आयोजकों ने बाबूभाई गहरवाल, बिपिन, बंटी, निरंजन, पवन व बजरंगदल के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया. रैली के दौरान पुलिस ने अनुशासनता के साथ नियोजन किया. रैली में कोई गड़बडी नहीं होनी दी. दिनभर सीपी भी बडनेरा में थे. उन्होंने समय-समय पर जानकारी ली.

इसके प्रति बडनेरा के पीआई भारती व पुलिस स्टाफ, शहर के सभी गणेशोत्सव मंडलों, दुर्गा मंडलों का भी आयोजकों ने आभार व्यक्त किया. रैली का यह प्रथम वर्ष था. अगले वर्ष भी सभी का सहयोग रहेगा, ऐसी विनती महाराणा प्रताप शोभायात्रा समिति बडनेरा, वीर राणा मंडल बडनेरा, गजानन महाराज संस्थान बडनेरा बजरंगदल प्रखंड ने

बस स्टैंड से वृद्ध लापता

अमरावती- बस स्थानक से सुरेश रामभाऊ तापस (76, नागपुर) शनिवार की सुबह लापता हो गए. उनके भाई दिलीप रामभाऊ तापस ने कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. बताया जाता है कि शनिवार की सुबह सुरेश तापस तलेगांव दशासर से अपनी बहू वृषाली विलास तापस के साथ 8.30 बजे के करीब अमरावती बस स्थानक पहुंचे. जहां सुरेश तापस ने बहू को ऑटो से भेजकर शहर में कुछ काम होने की बात कही. मुझे कोई लेने आ रहा है.

ऐसा बताते हुए बहू को ऑटो में बिठाकर घर भेज दिया किंतु वह घर नहीं लौटे. रात 9 बजे के करीब उनकी पत्नी ने परिजनों को फोन किया. सुरेश तापस के घर न आने की खबर मिलते ही उनके छोटे भाई दिलीप रामभाऊ तापस ने कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में स्टेशन डायरी में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रतन इंडिया के साथ पुनः पानी का समझौता

जल कटौती की मांग अमान्य, 87 दलघमी आरक्षित

प्रतिनिधि, 18 जून

अमरावती- रतन इंडिया बिजली प्रकल्प के लिए अपर वर्धा बांध से आरक्षित 87 दलघमी पानी में कटौती करने की विनती रतन इंडिया ने सिंचाई विभाग से की थी. राज्य के विधि व न्याय अधिकारी की ओर से अभिप्राय न आने के कारण उतना ही पानी देने का समझौता सिंचाई विभाग ने रतन इंडिया के साथ किया है. कंपनी की विनती पर 27 दलघमी पानी वापस मिलने से अपर वर्धा बांध क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र बढ़ेगा.

जिले के सबसे बड़े अपर वर्धा बांध से रतन इंडिया बिजली प्रकल्प में 87 दलघमी पानी देने का समझौता हुआ था. कंपनी ने 1325 मेगावाट क्षमता के चार प्रकल्प प्रस्तावित किए थे, लेकिन यह प्रकल्प पूर्ण क्षमता के साथ शुरू नहीं हुआ. जिसके कारण 87 दलघमी पानी की जरूरत नहीं रही. 4 महीने पूर्व रतन इंडिया ने इस आरक्षित पानी में से 27 दलघमी पानी वापस देने के लिए विनती पत्र सिंचाई विभाग को दिया था. इस पर राज्य के विधि व न्याय अधिकारियों का अभिप्राय नहीं आया.

जिसके कारण आरक्षित पानी में कटौती का निर्णय स्थानीय अधिकारी द्वारा नहीं लिया गया. नतीजतन मूल समझौते के अनुसार 87 दलघमी पानी देने का समझौता विभाग ने 22 मई को पुनः कंपनी के साथ किया. 2009 में प्रथम 87 दलघमी पानी बिजली प्रकल्प के लिए आरक्षित करने का समझौते हुआ था. इस समझौते के कारण आरक्षित पानी से 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को फटका लगा था. इस प्रकल्प को पानी ना दें, ऐसी मांग को लेकर किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था.

न्यायालय में मामला

रतन इंडिया ने पानी में कटौती करने की विनती की है. साथ ही समझौते के अनुसार पुनर्स्थापन खर्च देने से इंकार किया है. जिसके कारण यह मामला न्यायालय में गया है. उच्च न्यायालय ने कंपनी के पक्ष में फैसला दिया था. जिसके खिलाफ सिंचाई विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय में आह्वान दिया. वर्तमान में यह मामला प्रलंबित है.

सूचना

प्रतिदिन अखबार के पाठकों को सूचित किया जाता है कि वे इस अखबार में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों व लेखों में उल्लेखित उत्पादनों की गुणवत्ता जाँच-पड़ताल करने के बाद ही उसे खरीदने आदि के संबंध में निर्णय लें व आर्थिक व्यवहार करें. अपने उत्पाद अथवा सेवा के संदर्भ में विज्ञापनदाता जो दावे पेश करते हैं, प्रतिदिन अखबार उसकी कोई गारंटी नहीं देता. कृपया नोट करें कि विज्ञापित उत्पादों में किए गए दावों की पूर्ति यदि विज्ञापनदाता (उत्पादक) अथवा संबंधित नहीं करते तो उसके परिणामों के लिए प्रतिदिन अखबार के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक व मालिक जिम्मेदार नहीं होंग व्यवस्थापक

नांदगांव पेठ टोलनाका को लेकर दिल्ली में होगा मंथन

सांसद आनंद अड़सूल ने दिया आश्वासन , कृति समिति के पदाधिकारी रखेंगे अपनी बात

प्रतिनिधि, 18 जून

अमरावती - नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 6 पर नांदगांव पेठ में आईआरबी कंपनी का टोल नाका मोर्शी व वरुड़ वासियों के लिए विगत कई वर्षों से सिरदर्द साबित हो रहा है. केवल 11 किलोमीटर तक इस महामार्ग से गुजरने के लिए नागरिकों को 60 किलोमीटर तक के टोल नाके की रकम का भुगतान करना पड़ रहा है. मोर्शी व वरुड़ वासियों को इस टोलनाके से निजात दिलाने हेतु विगत कई वर्षों से संघर्ष कर रही कृति समिति के सदस्यों ने एक बार फिर रविवार को सांसद आनंद अड़सूल से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं. जिस पर सांसद अड़सूल ने इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी के साथ कृति समिति के पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली में आयोजित करने का आश्वासन दिया.कृति समिति के पदाधिकारी विशाल तिजारे, प्रा. अनंत बाजड़, पराग पांडे व प्रदीप बाजड़ ने सांसद अड़सूल की मुलाकात कर टोल नाके को लेकर विगत कई वर्षों से चल रहे संघर्ष पर विराम लगाते हुए मोर्शी वासियों को समस्या से निजात दिलाने हेतु चर्चा की. इस समय सांसद अड़सूल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी से दिल्ली में बैठक आयोजित कर सीधे पदाधिकारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने का आश्वासन देने के साथ ही उन्होंने तत्काल अपने पीए वड़तकर को केंद्रीय मंत्री गड़करी का समय लेने के निर्देश दिए. सांसद अड़सूल के इस आश्वासन के बाद कहीं ना कहीं लंबे समय से संघर्ष कर रही कृति समिति के पदाधिकारियों में उम्मीद की किरण जागी है.

टोल मुक्ति कृति समिति के पदाधिकारी प्रदीप बाजड़ ने बताया कि विगत रविवार 10 जून को वह सांसद अड़सूल से मुलाकात करने गए, किंतु वह अकोला के लिए अमरावती से प्रस्थान कर चुके थे. जिसके चलते उनकी मुलाकात नहीं हो पायी. इस समय उन्होंने भ्रमणध्वनि पर संपर्क करने पर सांसद अड़सूल ने इस संदर्भ में जल्द ही केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी से मुलाकात कर कृति समिति की मांगें रखने का आश्वासन दिया. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री गड़करी नागपुर रहते, कृति समिति के पदाधिकारियों की प्रत्यक्ष मुलाकात करवाने का भी प्रयास करेंगे. इस समय उन्होंने टोल नाके को लेकर 15 दिन का अल्टिमेटम देने के साथ ही तीव्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी भी दी थी. वहीं अब इस टोल नाके को लेकर कोई ना कोई हल निकलने का रास्ता दिखाई दे रहा है. बता दें कि इस महामार्ग से जिन लोगों को नागपुर की ओर यात्रा करना है, वह लोग रास्ते में लगने वाले टोल नाकों पर खुशी-खुशी चार्ज का भुगतान करते हैं. वजह यह है कि यहां से सभी सुविधाओं से सज्ज फोरलेन सड़क का निर्माण कंपनी द्वारा किया गया है. जिसके चलते यहां से यात्रा करना सुखद मालूम पड़ता है, किंतु इसके विपरीत मोर्शी व वरुड़ से आना-जाना करने वाले नागरिकों को एकमात्र महामार्ग क्र. 6 का ही विकल्प है. अमरावती से नांदगांव पेठ तक 11 किलोमीटर तक महामार्ग से गुजरने के बाद यहां के नागरिकों को आगे का सफर सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग द्वारा निर्माण किए गए सड़क से करना पड़ता है. महामार्ग से आगे सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि यहां से वाहन चलाना मुश्किल साबित होता है. यहां तक कि इस मार्ग पर कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, किंतु इन सब बातों को नजरअंदाज कर मात्र 11 किमी की यात्रा के लिए मोर्शी व वरुड़ तहसील से आना-जाना करने वाले नागरिकों को पूरे 60 किमी के टोल नाके का भुगतान करना पड़ता है. जिसके चलते विगत कई वर्षों से नागरिकों में आक्रोश है.